THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Yes.

(d) Saurashtra Chamber of Commerce have been replied that there is no proposal to change headquarters of Bhavnagar Division.

1 अप और 2 डाउन कालका मेल में यात्रियों को दिया जाने वाला भोजन

3793. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में पेंट्री कारों में यात्रियों को दिया जाने वाला खाना 'बेस किचन' का बना होता है ।

(ख) क्या 'बेस किचन' का बना खाना आसानी से पच जाता है और पोषक होता है तथा कालका मेल में प्रतिदिन मुगलसराय, इलाहाबाद और टूंडला पर दिया जाता है ।

(ग) क्या 1 अप और 2 डाउन कालका मेल में पैंट्री कार 'बेस किचन' से खाना नहीं दिया जाता है और घटिया किस्म का खाना गंदे और जंग लगे एल्यूमिनियम के बर्तनों में दिया जाता है, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नियमों का उल्लंघन करने के कारण ठेकेदार का एकाधिकार समाप्त करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उत्तर रेलवे में 2 गाड़ियां हैं जिनमें पेंटरी कार सेवा की व्यवस्था है । इनमें से एक मुगलसराय और दिल्ली के बीच चलने वाली हावड़ा-दिल्ली-कालका मेल और दूसरी गोमती एक्सप्रेस है । इन गाड़ियों में किसी में भी खाना आधार रसोईघरों से नहीं लिया जाता है ।

(ख) और (ग) आधार रसोईघरों में तैयार किया गया खाना बढ़िया किस्म का होता है । 1 अप 2 डाउन कालका मेल में लगायी जाने वाली पेंटरी कार में पहले से पका खाना इलाहाबाद और टूंडला में स्थित आधार रसोईघरों से सप्लाई किया जाता था । 1-4-80 से पेंटरी कार के ठेकेदार को पेंटरी कार में ही स्वास्थ्यकर खाना बनाने की अनुमति दे दी गई है । पहले, जुलाई 1977 में उत्तर रेलवे ने 1.70 रुपये प्रति थाली की दर से जनता खाना शुरू किया था और पेंटरी कार के ठेकेदार को भी 1 अप/2 डाउन कालका मेल में जनता खाना बेचने की अनुमति दे दी गयी थी । तब से, इलाहाबाद और टूंडला में स्थित आधार रसोईघरों से पहले से पका खाना उठाने के अतिरिक्त, ठेकेदार पेंटरीकार में ही खाना पकाता चला आ रहा है । परिणामस्वरूप आधार रसोईघरों से थाली खाना उठाने की मांग घट गई । आधार रसोईघरों से खाना उठाने और गाड़ी में इन्हें परोसने की ठेकेदार की मिश्रित पद्धति असंतोषजनक नहीं थी और खाने की संतोषप्रद सेवा के लिए किसी की जिम्मेवारी निर्धारित करना संभव नहीं था । 1 अप 2 डाउन कालका मेल में खान-पान सेवा में सुधार करने के लिए 1-4-80 से पेंटरी कार में ही खाना बनाने और कुछ अन्य मदों को भी बेचने की पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार को देने का निर्णय किया गया था । यद्यपि 1 अप/2 डाउन कालका मेल में खाने की मांग की पूर्ति पेंटरी कार में की जाती है, फिर भी आर्डर देने पर अल्पाहार गृहों से भी खाना सप्लाई किया जाता है । यद्यपि सुधार की गुंजाइश है, फिर भी 1 अप/2 डाउन कालका मेल की पेंटरी कार से सप्लाई किये जाने वाले खाने की किस्म संतोषजनक है और खाना स्टेनलेस स्टील और हिन्डोलियम की थालियों में दिया जाता है जिनमें जंग नहीं लगता है और जो गंदी नहीं होती है ।

(घ) इस खान-पान ठेकेदार का रेलों पर कोई एकाधिकार नहीं है । नियम का उल्लंघन करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है ।

Rail Line up to Chickmagalur

3794. SHRI D. M. PUTTE GOWDA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Chickmagalur District Headquarters is not connected by Railway;

(b) whether Government are aware that people of Chickmagalur District are pressing for the same for the last twenty five years;

(c) whether Government are also aware that there are no major industries in Chickmagalur due to non-existence of railway line; and

(d) if so, whether Government propose to take up the railway line now?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (d) Representations have been received for

the construction of a rail line from Kadur to Chickmagalur. No such proposal is under consideration at present. In view of the difficult resources position, it will not be possible to take up the proposal at present.

रेलवे फाटक

3795. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने रेल फाटक है जिनको बन्द करने एव खोलने के लिए कोई रेल कर्मचारी नियुक्त नही है ;

(ख) ऐसे फाटकों पर रेल कर्मचारियो की नियुक्ति करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ;

(ग) इन सभी फाटको पर कर्मचारियो की नियुक्ति पर कुल कितना वार्षिक व्यय होगा ;

(घ) क्या देश में बिना कर्मचारी वाले इतने अधिक रेल फाटक होते हुए जब नए फाटक की मांग की जाती है तो मंत्रालय वहां वर्षो तक कर्मचारी रखने के अनुमानित व्यय की लोगो तथा राज्य सरकारो से मांग करता है; और

(ङ) क्या फाटक बनाने की सुविधा उपलब्ध कराने का खर्चा जनता से मांगने की प्रथा बन्द की जाएगी और महत्वपूर्ण स्थानों पर नए फाटक बनाए जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेलो पर 31-3-1979 को बिना चौकीदार वाले 'ग' श्रेणी के समपारो की सख्या 21595 थी ।

(ख) बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करना एक सतत प्रक्रिया है । यातायात संगणना द्वारा कुल समपारों के पांचवे भाग की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है और बिना चौकीदार वाले जिन समपारों पर चौकीदार रखने का औचित्य पाया जाता है, उनके लिए धन उपलब्ध होने पर राज्य सरकार के परामर्श से एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्था की जाती है । बहरहाल, बिना चौकीदार वाले जिन समपारों पर अधिक दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है, वहां चौकीदार की व्यवस्था करने को प्राथमिकता दी जाती है ।

(ग) यदि इन सब समपारों पर चौकीदार रखे जाते हैं तो निर्माण की प्रारम्भिक लागत के रूप में लगभग 150 करोड़ रुपये और वार्षिक अनुरक्षण तथा परिचालन प्रभार के रूप मे प्रति वर्ष 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे ।

(घ) भारतीय रेल अधिनियम के अनुसार, रेल प्रशासनो को अपनी लागत पर उन समपारों का प्रबन्ध और अनुरक्षण करना होता है । जिन्हे राज्य सरकारें रेलवे लाइन के निर्माण के समय या उसे यातायात के लिए खोल दिये जाने के बाद 10 वर्षों के भीतर रेल लाइन के निर्माण से हुए व्यवधान को दूर करने के लिए आवश्यक समझती है । रेलवे लाइन को यातायात के लिए खोल दिये जाने के 10 वर्ष बाद किसी भी नये समपार की लागत सुविधा की अपेक्षा रखने वाली राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वहन की जानी अपेक्षित है । अत: रेलवे लाइन को यातायात के लिए खोल दिये जाने के 10 वर्ष बाद जो नये समपार अपेक्षित होते हैं, उनके प्रस्ताव सबधित राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किये जाते हैं जिन्हे उनके निर्माण और अनुरक्षण की लागत वहन करने का वचन देना होता है । समपार पर चौकीदार रखा जाये या नही, यह रेल और सडक यातायात के घनत्व, दृश्यता और अन्य स्थानीय कारणों पर निर्भर करता है ।

(ङ) प्रश्न नही उठता ।

Sakri-Hasanpur Line

3796. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) The details including the time schedule for the construction of Sakri-Hasanpur new railway line under Samastipur Division of the North Eastern Railway; and

(b) what are the hurdles in the way of completing the construction by the year end?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b). The construction of a new MG line between Sakri and Hasanpur is an approved work and a beginning is expected to be made or this work in 1980-81. An outlay of Rs. 17.99 lakhs has been proposed in the 1980-81 budget for this project. No target date for completion can be fixed at this stage.